>

Title: Regarding delay in notification of 9th Wage Agreement in coal India.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से साढ़े चार लाख भारत सरकार के कोल इंडिया के मजदूरों का विषय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। कोयला मंत्रालय से संबंधित जो लगभग साढ़े चार लाख श्रमिक हैं, उनका नौवां वेतन समझौता दि. 01.07.2011 से लागू किया जाना है। परंतु इस समझौते को लेकर केन्द्र सरकार के कोयला मंत्रालय के द्वारा अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। कोल इंडिया के चेयरमैन के द्वारा अखबारों में लगातार यह बयान दिया जा रहा है कि यूनियनों के आपसी विवादों के चलते नौवें वेतन समझौते में विलम्ब होगा।

हमारा आपसे आग्रह है कि यूनियनों का आपस का यदि कोई विवाद है तो उससे जेबीसीसीआई के संख्या बल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चूंकि यूनियनों के महासंघों के सदस्यों की जो संख्या है, उसमें आईएनटीयूसी के छः हैं, एआईटीयूसी के तीन हैं, एचएमएस के तीन हैं, बीएमएस के तीन हैं और सीआईटीयू के तीन हैं। वर्तमान में नौवां वेतन समझौता किन कारणों से कामगारों के विरुद्ध है, इसके लिए कोयला मंत्रालय को विशेष रूप से इस पर ध्यान देना होगा, ताकि नौवे वेतन समझौते की समय पर अधिसूचना जारी की जा सके।

महोदया, चूंकि हम लोग कोयलांचल क्षेत्र से आते हैं और वहां के मजदूरों की आज के समय में जो दयनीय स्थिति है, यदि यह समझौता समय पर लागू नहीं किया जायेगा तो आने वाला समय मजदूरों के लिए बहुत कष्टदायक होगा। धन्यवाद।

सभापति महोदया : श्री बसुदेव आचार्य का नाम इस विषय से सम्बद्ध किया जाता है।